VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
J
P
26 AUG 2022
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1835)

Name of Candidate	SURYA GODARA		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	125093
Center	JAIPUR	Date	26/08/22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

VisionIAS

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. The withdrawal of general consent to the CBI by certain state governments in India threatens the spirit of cooperative federalism in India. Discuss.

(150 words) 10

भारत में कुछ राज्य सरकारों द्वारा सी. बी. आई. से सामान्य सहमति वापस लेना भारत में सहकारी संघवाद की भावना के लिए खतरा उत्पन्न करता है। चर्चा कीजिए।

दिल्ली विशेष पुलिस बल स्थापना, 1946 के तहत CBI का गठन किया गया है। यह भ्रष्टाचार के मामलों में CBI को केंद्रीय कर्मचारियों की जाँच का अधिकार प्रदान करता है।

* विवाद के बिंदु - ① सामान्य सहमति वापस लेने से केंद्र-राज्य टकराव की स्थिति।
② विशिष्ट मामलों में अनुमति से इंकार करना
→ बंगाल, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लेना।

* संघवाद हेतु खतरा
→ सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध।
→ केंद्रीय कर्मचारियों की जाँच हेतु केंद्र

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकार की शक्तियाँ।

→ CBI द्वारा राजनीतिक हितों को महत्व देने के कारण संदेह।

→ केंद्र एवं राज्यों में टकराव के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों की क्षति।

आगे की राह

① CBI को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना।

② नियुक्ति में पारदर्शिता लाना (सर्चिंग समिति)

③ स्वतंत्र संस्था के रूप में CBI की छवि।

④ चयनित रूप से केस के चयन की प्रवृत्ति पर अंकुश।

अतः भ्रष्टाचार तथा अपराध को समाप्त करने हेतु CBI को मजबूत कर सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Stating the sources of finance for local self-governments in India, suggest ways to strengthen their financial position. **(150 words) 10**

भारत में स्थानीय स्व-शासी सरकारों के लिए वित्त के स्रोतों का उल्लेख करते हुए, उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपाय सुझाइए।

73 वें तथा 74 वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतें तथा नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के गठन का प्रावधान है। अनु. 243 I में राज्य वित्त आयोग का गठन वर्णित है।

वित्त के स्रोत

① केंद्रीय वित्त आयोग (अनु. 280) द्वारा प्रदत्त अनुदान

② केंद्रीय योजनाओं से जुड़ा वित्त (90% वित्त शर्त सहित)

③ राज्य सरकारों द्वारा बजट आवंटन

④ कर के स्थानीय स्रोत – सिंचाई कर

* चुनौतियाँ → वित्तीय विकेंद्रीकरण का अभाव
→ वित्तीयन के अपारदर्शिता (खातों की मैनुअल

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आडिटिंग)

→ अपर्याप्त शक्तियों का हस्तांतरण।

→ राज्य एवं केंद्रीय पूल की राशियाँ अधिकांशतः शर्तों सहित।

उपाय

① 15 वें वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग से जोड़ना।

② 2nd ARC की 6th रिपोर्ट के अनुरूप वित्तीय विकेंद्रीकरण

③ बॉटम-अप एप्रोच आधारित विकास।

④ आंतरिक राजस्व संग्रहण तंत्र को बढ़ावा

⑤ राज्य वित्त आयोगों की नियमित नियुक्ति

⑥ राज्यों को GST क्षतिपूर्ति।

अतः राजकोषीय संघवाद की भावना के अनुरूप ग्राम राज के माध्यम से स्वराज के संकल्प को सिद्ध करने की आवश्यकता है।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Cabinet Committees play an important role in reinstating collective responsibility and principle of homogeneity of the Executive in the Indian Parliamentary system. Elucidate. **(150 words) 10**

भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडलीय समितियां सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका की एकरूपता के सिद्धांत को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्पष्ट कीजिए।

भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों हेतु विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इस संदर्भ में मंत्रिमंडलीय समितियाँ जवाबदेही का महत्वपूर्ण तंत्र है।

- प्रतिवर्ष सरकार द्वारा गठित (एक वर्ष का कार्यकाल)
- कुल 8 मंत्रिमंडलीय समितियाँ

(*) सामूहिक उत्तरदायित्व लागू करने में भूमिका

1. विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा
2. कार्यपालिका पर प्रश्नों का उत्तर देने का दबाव
3. पारदर्शिता एवं कार्यान्वन हेतु संस्थागत तंत्र।
4. लोक निधि का सकारात्मक उपयोग सुनिश्चित करना

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⊛ **कार्यपालिका की उत्तरदायित्वता**

→ विधायिका के सदस्य संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी

→ सरकार के आंतरिक उत्तरदायित्व की स्थापना में सहायक

चुनौतियाँ
- पारदर्शिता का अभाव
- अपर्याप्त चर्चा
- कम बैठकें
- सदस्यों की अनुपस्थिति
- सार्वजनिक प्रकाशन का अभाव

आगे की राह ① विभागीय समितियों की कार्यप्रणाली हेतु मानक नियमावली।

② जन भागीदारी एवं विचार विमर्श को प्रोत्साहन।

अतः विभागीय समितियाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा संसदीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. There is a need to overhaul the public procurement and project management (PPPM) framework of India for faster, efficient and transparent execution of government projects. Comment.

(150 words) 10

सरकारी परियोजनाओं के तीव्र, कुशल और पारदर्शी निष्पादन के लिए भारत के सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन (PPPM) ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

भारत में सार्वजनिक खरीद में विद्यमान चुनौतियाँ व्यापक भ्रष्टाचार का कारण बनी हुई है (कैग रिपोर्ट)

* सुधार की आवश्यकता के कारण

① लोक निधि के प्रयोग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयास करना

② व्यापक विवादों को सीमित करना

③ क्रोनी कैपिटलिज्म की उपस्थिति।

④ भ्रष्टाचार, लोक कल्याण के मार्ग में बाधक

⑤ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना

⑥ 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन'

VisionIAS

(6) उपाय ① खरीद प्रक्रिया को ऑनलाइन करना (GeM पोर्टल)

② खरीद प्रक्रिया हेतु मानकों का विकास, तथा निष्पक्ष तीसरे पक्ष द्वारा जांच

③ पारदर्शी शासन हेतु सेवोत्तम मॉडल को अपनाना

④ अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण हेतु सामाजिक पूंजी का विकास

⑤ ई-गवर्नेंस पर ईमानदार कार्यान्वयन के अनुरूप खरीद प्रणाली हेतु व्यापक ढांचा।

अतः सुशासन की स्थापना तथा भ्रष्टाचार की समाप्ति हेतु आमूलचूल परिवर्तनों की आवश्यकता है।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Adequate measures are required to overcome the challenges and vulnerabilities associated with undertaking social accountability initiatives and institutionalising them. Elaborate. **(150 words) 10**

सामाजिक जवाबदेही पहलों को शुरू करने और उन्हें संस्थागत बनाने से जुड़ी चुनौतियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए पर्याप्त उपायों की आवश्यकता है। सविस्तार वर्णन कीजिए।

सामाजिक जवाबदेही से तात्पर्य नौकरशाही तथा शासन के कार्यों के जन उत्तरदायित्व ग्रहण से है। उदा.- सामाजिक अंकेक्षण, RTI Act, 2005

बाधाएं

शुरू करने में

① मानक ढांचे की अभाव
② सामाजिक जागरूकता में कमी
③ अपर्याप्त प्रोत्साहन
④ मापन संभव नहीं
⑤ शासन में व्याप्त पदानुक्रम
⑥ नवाचार तथा परिवर्तन का प्रतिरोध
⑦ अपर्याप्त कार्यान्वयन

संस्थागत बनाने में

(i) सामाजिक जवाबदेही का वस्तुनिष्ठ न होना
(ii) सभी की संतुष्टि संभव नहीं,
(iii) बड़ा तंत्र, पुनः वित्तपोषित बाधियों तथा भ्रष्टाचार का कारक बनना।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपायों की आवश्यकता → सुशासन की स्थापना
→ सामाजिक-आर्थिक न्याय की आपूर्ति
→ सेवा वितरण / वितरणाधिकार
→ नौकरशाही को भ्रष्टाचार से मुक्त करना
→ बेहतर सेवा आपूर्ति तंत्र का अभाव।

उपाय : जो अपेक्षित है

① संवेदनशील मॉडल (सात चरणीय मॉडल)

② सुशासन मॉडल के तहत प्रभावी पारदर्शिता

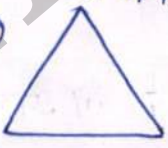

③ RTI Act, 2005 को सशक्त करना, लोगों की जागरूकता बढ़ाना।

④ सामाजिक अंकेक्षण ढांचे को मजबूत करना

⑤ नागरिक चार्टर (पंचायतों हेतु आदर्श चार्टर)

अतः शासन को नागरिक केंद्रित बनाने हेतु 2ARC 4th रिपोर्ट : शासन में नैतिकता के अनुपालन की आवश्यकता है।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. In view of the recent Parliamentary Standing Committee report, discuss the issues faced by the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) and suggest measures that can be adopted to strengthen it. **(150 words) 10**

एक संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की विवेचना कीजिए और इसे मजबूत बनाने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

NCST का गठन 89CA के तहत अनु. 338क से किया गया है। यह भारत की 8.08% जनजातीय जनसंख्या के हितों के संरक्षण हेतु अधिदेशित है।

* **रिपोर्ट में वर्णित मुद्दे**

① विगत चार वर्षों में NCST की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई।

② वित्त वर्ष 2021 में केवल 4 बैठकें।

③ रिक्त पड़े पद (मानदण्ड स्पष्ट नहीं)

④ संस्थागत क्षमता का अभाव
  └ अपर्याप्त वित्त

⑤ रिपोर्ट पर अपर्याप्त चर्चा

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपाय ① रिपोर्ट समय पर सदन में प्रस्तुत हो (3 माह के भीतर)
② चर्चा हेतु 2½ घंटे निर्धारित करना।
③ रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखना।
④ समय, रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही को बताएँ, अन्यथा लिखित स्पष्टीकरण दें।
⑤ नियमित बैठकों का आयोजन
⑥ मानकों को सरल कर पदों को भरना
⑦ मानव संसाधन क्षमता का सृजन।

अतः NCST को मजबूत कर समाज के हाशिये पर स्थित जनजातियों को सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सकता है। इस दिशा में दिलीप सिंह भूरिया (1995) समिति की सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. While the Mid-Day Meal scheme was aimed at fulfilling the nutritional needs of students, it is far behind in achieving this objective. Discuss. Also, suggest remedial measures in this context. **(150 words) 10**

यद्यपि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था, किंतु इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह काफी पीछे है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए।

खाद्य सुरक्षा Act, 2013 तथा पोषाहार वितरण योजना के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की 101/116 रैंक चिंताजनक है।

1995 में प्रारम्भ मिड डे मील योजना पोषणयुक्त भोजन तथा साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रारम्भ की गई थी।

(*) कमियाँ (i) पोषणयुक्त भोजन की कमी

(ii) FCI द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न की गुणवत्ता का अभाव।

(iii) गुणवत्ता पर बल नहीं (पोषक तत्वों हेतु हरी सब्जियाँ, मोटे अनाज की अनदेखी)

VisionIAS

(iv) नीति आयोग की MPI रिपोर्ट के अनुसार बिहार मॉडल अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है।

उपाय

① पोषक भोजन - फोर्टिफाइड चावल, मोटा अनाज वितरण + पोषण वाटिकाएँ
② तिथि भोजन प्रारम्भ करना।
③ अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान
④ DBT के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्त तन्त्र FPO के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद।
⑤ भोजन सहायकों के वेतन में बढ़ोतरी।
⑥ महिला SHG के माध्यम से खाद्य गुणवत्ता

अत: पोषाहार तथा जीवन स्तर (अनु० 47) को उच्च स्तर पर बनाए रखने हेतु राज्य की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Sexual and reproductive health and rights (SRHR) remain critical for the attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs). In this context, discuss the impediments in the fulfilment of SRHR in India. Also, mention the steps that can be taken in this regard. **(150 words) 10**

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (SRHR) महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में, भारत में SRHR की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

लैंगिक पूर्वाग्रह तथा प्रजनन अधिकारों के सम्बंध में जागरूकता का अभाव SDG प्राप्ति में बाधक है। SDG-5 के अनुरूप लैंगिक समानता प्राप्त करने हेतु इन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

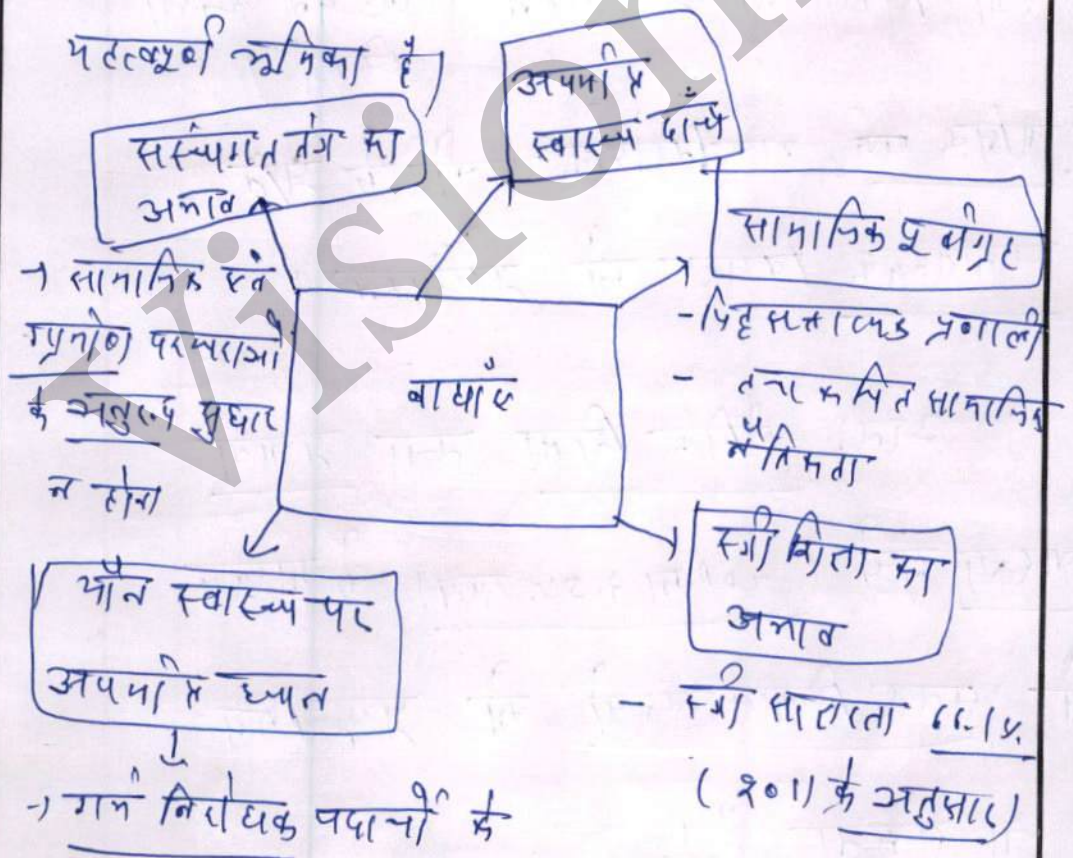

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(*) [उठाए जा सकने योग्य कदम]

(1) लैंगिक शिक्षा (नीति आयोग) – प्रजनन अधिकारों के प्रति जागरूकता + विद्यालय एवं कॉलेज पाठ्यक्रम)

(2) सामाजिक पूर्वाग्रह निषेध – प्रचार अभियान, नुक्कड़ नाटक का आयोजन।

(3) आशा सहयोगिनी तंत्र को मजबूत करना।

(4) स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन (पैडमैन जैसी फिल्में)

(5) मासिक धर्म, गर्भनिरोधक पदार्थों के प्रति सकारात्मक विमर्श को प्रोत्साहन।

अतः लैंगिक शिक्षा तथा प्रभावी स्वास्थ्य तंत्र (GDP का 2.5% व्यय) के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. State the functions of the United Nations Human Rights Council. Also, discuss the issues faced by the Council in the promotion and protection of human rights around the globe. **(150 words) 10**

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, विश्व भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण में परिषद द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की विवेचना कीजिए।

UNHRC का गठन 2006 में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा से सदस्यों का चुनाव किया जाता है।

कार्य
1. विश्व में मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करना।
2. मानवाधिकार संरक्षण अभियानों को प्रारम्भ करना (कार्यों में सहत)
3. मानवाधिकारों हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहमति का निर्माण करना।
4. मानवाधिकार उल्लंघन वाले देशों के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा (इजरायल - फिलिस्तीन संघर्ष)

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ ① सदस्यों का चयन, विदेश नीति के पारस्परिक हितों के अनुरूप जिस कारण दोषपूर्ण (चीन में उइगर उत्पीड़न पर चुप्पी) सदस्यों का समावेश (वेनेजुएला)

② कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं।

③ देशों को केवल सलाह प्रदान करना।

④ राहत कार्यों हेतु विकसित देशों के वित्त पर निर्भरता।

⑤ इजराइल के मुद्दे पर USA का इससे बाहर निकलना।

आगे की राह ① UN चार्टर तथा मानवाधिकारों के घोषणापत्र के अनुरूप स्वीकृत ढांचे का गठन।

② देशों में सहयोग + वित्त में सहयोगात्मकता।

मानवाधिकारों की रक्षा ग्लोबल युग में महत्वपूर्ण आयाम है जिसके बिना सतत विकास जैसे लक्ष्य प्राप्त करना कठिन।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. West Asia is an important strategic region for India with profound geo-political and geo-economic significance. Discuss. **(150 words) 10**

अत्यधिक भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक महत्व के कारण पश्चिम एशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है। चर्चा कीजिए।

पश्चिमी एशिया में अरब देश, ईरान, इजरायल जैसे देश शामिल है जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

* भू-राजनीतिक महत्व - ① लुक वेस्ट नीति

② I2U2 गठबंधन, ईरान में चाबहार बंदरगाह, UAE के साथ व्यापक व्यापार समझौता

③ OIEC देशों तथा अरब परिषद् के साथ सम्बंध।

④ अब्राहम समझौते हेतु महत्वपूर्ण।

⑤ चीन की BRI को संतुलित करना।

⑥ ईरान - सऊदी - इजरायल सम्बंधों में संतुलन।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(*) मू-आर्थिक ① UAE - तेल आपूर्ति में तीसरा सबसे बड़ा देश, प्राकृतिक गैस का आपूर्तिकर्ता, भारत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय (18 बिलियन डॉलर रेमिटेंस)

② ईरान - TAPI प्रोजेक्ट, तेल आपूर्ति

③ इज़राइल - अब्राहम समझौते के पश्चात बदलते समीकरण, राफेल विमान, 8.6 बिलियन डॉलर व्यापार, भारतीय हीरों का महत्वपूर्ण खरीददार।

④ सऊदी अरब - हज यात्रा में बड़ी संख्या में भारतीय।

अतः भारत को लुक वेस्ट नीति को रहे प्रशांत विज़न से संतुलित कर, अधिक सहयोगात्मक बनाने की आवश्यकता है।

VisionIAS

11. Disenfranchising prisoners desecrates a cherished value in a democracy i.e. 'right to vote', which should be guarded earnestly. Discuss in the light of The Representation of The People Act, 1951. **(250 words) 15**

कैदियों को मताधिकार से वंचित करना वस्तुतः लोकतंत्र के एक प्रशंसनीय मूल्य, अर्थात् "मतदान के अधिकार" का अपमान करना है, जिसकी गंभीरतापूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के आलोक में चर्चा कीजिए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनाव में मतदान के मुद्दों को सम्बोधित करता है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार (अनु. 325) के तहत संवैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए।

(a) कैदियों के मताधिकार के पक्ष में तर्क

① विचाराधीन कैदी – NCRB के अनुसार 65% से अधिक कैदी विचाराधीन।

② मानवाधिकारों पर बोझिल पग → मतदान का अधिकार, अनिवार्य मूल अधिकार।

③ अभिव्यक्ति की आजादी तथा वोट देने

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

का अधिकार, सामान्य नागरिकों की तरह कैदियों को भी है।

चुनौतियाँ

(i) RPA Act, 1951 में इस सम्बन्ध में प्रावधान का अभाव।

(ii) चुनाव की व्यवहार्यता (चुनाव मतदान किस प्रकार, कैदी अखिल भारतीय हो सकते हैं)

(iii) अपराधी तत्वों की हिस्सेदारी, राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण (विधि आयोग 170 वीं रिपोर्ट)

उपाय → कानून में संशोधन

→ गंभीर अपराध वाले कैदियों को छोड़कर अन्य हेतु मतदान की स्वीकृति

↳ विचाराधीन कैदी

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ कानून में व्यापकता लाना (UN चार्टर के अनुरूप सुधार)

अतः चुनाव सुधार की दिशा में कोशिशों द्वारा मतदान सकारात्मक सामाजिकरण का वाहक बन सकता है तथा न्याय की सुधारात्मक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है।

VisionIAS

12. There are similarities and interactions between the affirmative action adopted by India and USA owing to similar historical injustices faced by their respective vulnerable groups. Discuss. **(250 words) 15**

भारत और यू. एस. ए. के सुभेद्य समूहों द्वारा सामना किए गए एकसमान ऐतिहासिक अन्याय के कारण, इनके द्वारा अपनाई गई सकारात्मक कार्रवाई के बीच समानताएं हैं और इनका एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। चर्चा कीजिए।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा USA विश्व का सबसे पुराना स्थापित लोकतंत्र है (1783, अमेरिका की क्रांति)। दोनों देशों का संविधान लोकतांत्रिक प्रणाली, मूल अधिकारों के मूल्यों से निर्देशित है।

① एकसमान ऐतिहासिक अन्याय

① दोनों ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के शिकार [भारत - धन का बहिर्गमन
USA - बिना प्रतिनिधित्व करों कर नहीं]

② रंगभेद तथा अस्पृश्यता की शोषणमूलक प्रणाली।

③ नागरिक अधिकारों हेतु लंबी लड़ाई

Visionias

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तत्पश्चात् स्वतंत्रता की प्राप्ति।

④ शासन के सामंतवादी ढांचे के उत्पीड़न के शिकार।

⑤ व्यापक विविधता युक्त सामाजिक संरचना के कारण 'फूट डालो और राज करो' का शिकार।

दोनों संविधान में समानताएं

① व्यापक मूल अधिकार → USA में मूल अधिकारों का बोधणापत्र, भारत में भाग-3 अनु० 12-35 तक।

② सामाजिक न्याय [भारत → AR.17 (अस्पृश्यता का अंत)
USA → रंगभेद प्रतिषेध।
↳ (1960 के दशक) के आंदोलन

③ न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद

⑤ अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (अनु 29-30)

इन समानताओं के बावजूद USA में अध्यक्षात्मक प्रणाली विद्यमान है तथा अमेरिका की संघीय प्रणाली (प्रांतों के समान महत्व पर आधारित) भारत से भिन्न है।

परंतु समानताओं के तत्वों ने भारत को अग्रणी लोकतांत्रिक देशों में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Objections to domicile-based reservation in private sector jobs on the grounds of constitutional equality and freedom are misplaced. Critically discuss. **(250 words) 15**

संवैधानिक, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर निजी क्षेत्रक की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण पर आपत्ति अनुचित है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

संविधान का अनु. 14, विधि के समक्ष समता तथा अनु. 16 अवसरों की समानता की बात करते हैं। आरक्षण, सकारात्मक रूप से समानता स्थापित करने का मार्ग है। इंद्रा साहनी वाद (1992) ने इसके महत्व को स्वीकार किया है।

⊛ अधिवास आधारित आरक्षण के पक्ष में तर्क

① अनु. 16 सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है।

② पिछड़े राज्यों में नौकरियों पर अप्रवासियों के कब्जे के कारण स्थानीय नौकरियों की क्षति।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ राज्य के सीमित रोजगार संसाधन

④ निजी क्षेत्र के सहयोग के माध्यम से समग्र आर्थिक विकास (हरियाणा आरक्षण विधेयक)

★ **विपक्ष में तर्क** ① आरक्षण 50% से ऊपर नहीं (इंदिरा साहनी वाद 1992)

② भूमिपुत्र की अवधारणा क्षेत्रीयता की प्रतिहिंसा (महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के विरुद्ध)

③ संवैधानिक नैतिकता तथा AR. 16, 19, 21 की मूलभावना के विरुद्ध।

④ उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विधेयकों पर रोक (तमिलनाडु आरक्षण विधेयक)

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑤ क्षेत्रीय राजनीति के कारण राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक।

अतः निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण का विरोध निराधार नहीं है। आरक्षण की नीतियाँ व्यापक देशहित को निर्देशित करने वाली होनी चाहिए।

इस दिशा में उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शक सिद्धांत (हरियाणा आरक्षण विधेयक) भी महत्वपूर्ण है। संवैधानिक नैतिकता की स्थापना करना महत्वपूर्ण है।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. There have been arguments that sedition law is an attack on the very foundation of India's liberal democratic principles, as enshrined in the Constitution. Do you agree? **(250 words) 15**

ऐसा तर्क दिया जाता है कि राजद्रोह कानून भारत के उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर हमला है, जैसा कि संविधान में निहित हैं। क्या आप सहमत हैं?

IPC की धारा 124 A में राजद्रोह का प्रावधान है, जो इसे गैर जमानती तथा संज्ञेय अपराध घोषित करता है।

(क) राजद्रोह कानून की आवश्यकता

(i) विधि के शासन की स्थापना
(ii) देश विरोधी तत्वों से निपटना
(iii) सार्वजनिक आदेश, लोक व्यवस्था जैसे युक्तियुक्त निर्बंधन
(iv) पुलिस बलों का सशक्तिकरण।

परंतु इन आवश्यकताओं के बावजूद अपनी औपनिवेशिक प्रवृत्ति तथा व्यापक दुरुपयोग की आशंका के चलते

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष खतरा है -

① बढ़ते मामले → 2016-19 के बीच 160% वृद्धि (NCRB)

② अभियोजन की दर न्यूनतम - केवल 3.1% अभियोजन दर (NCRB)

③ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन
 L विधि आयोग 2018 की रिपोर्ट

④ नागरिक अधिकार तथा कानून व्यवस्था के संतुलन का अभाव (अमीश देवगन मामला, 2020)

⑤ दुरुपयोग के बढ़ते अवसर तथा राजनीतिक दुरुपयोग का माध्यम (SC का हालिया निर्णय)

VisionIAS

आगे की राह ① फ्री स्पीच तथा हेट स्पीच में अंतर करना महत्वपूर्ण (अमीश देवगन वाद, 2020)

② कानून को निरस्त करना (विधि आयोग)

③ फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के माध्यम से दुरुपयोग का निषेध।

④ गैर कानूनी गतिविधियों को UAPA के तहत निपटना।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवंत लोकतंत्र का मूल है जिसे संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Despite Government e-Marketplace facing certain challenges, it has brought about a significant improvement in the procurement of goods and services by various government agencies. Discuss. **(250 words) 15**

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस द्वारा कुछ चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, इन्होंने विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में महत्वपूर्ण सुधार किया है। चर्चा कीजिए।

GeM पोर्टल - गट सरकार से व्यवसायों हेतु ई गवर्नेंस का महत्वपूर्ण भाग है। शासन में पारदर्शिता तथा लोक उत्तरदायित्व के वृद्धि के माध्यम से सुशासन की स्थापना की ओर अग्रसर करता है।

* महत्वपूर्ण सुधार

(i) विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों द्वारा तय सीमा की खरीद हेतु पोर्टल का उपयोग।

(ii) 'आत्मनिर्भर भारत' के अनुरूप

(iii) 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'

(iv) वोकल फोर लोकल का माध्यम।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(v) सरकारी निविदाओं में पारदर्शिता का समावेश (CAG रिपोर्ट)

(vi) बिचौलियों की कमी से बेहतर उत्पाद गुणवत्ता तथा वित्त का समुचित उपयोग।

सामना की जाने वाली चुनौतियां

(i) बड़े व्यापारिक समूहों का आधिपत्य।

(ii) सरकारी निविदा में व्याप्त खामियां।

(iii) स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन का अभाव

(iv) सभी मंत्रालयों की खरीद तक विस्तार का अभाव।

(v) तकनीकी मुद्दे – स्थानीय लोगों की अपर्याप्त पहुंच, व्यापक जानकारी का अभाव

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह

(i) निविदाओं की खामियों को दूर करना (व्यवसाय अनुकूल नीति/निर्माण)

(ii) राज्यों तक विस्तारित करना।

(iii) उत्पादों की गुणवत्ता तथा निगरानी हेतु प्रभावी तंत्र (ऑनलाइन ऑडिट, मानक एवं लेबलिंग)

(iv) स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता।

अतः सुशासन की स्थापना हेतु पारदर्शी खरीद एक महत्वपूर्ण पहल है जो सेवा गुणवत्ता के साथ लोकनिधि के समुचित उपयोग को बढ़ावा देगा।

VisionIAS

16. A reformed system of recruitment, training and evaluation needs to be put in place to take forward the development of a highly efficient and accountable civil service. Discuss in the context of India. **(250 words) 15**

अत्यधिक कुशल और जवाबदेह सिविल सेवा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और मूल्यांकन की एक संशोधित प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

सरदार पटेल ने लोक सेवाओं को 'स्टील फ्रेम' की संज्ञा दी है। नौकरशाही का विकास सुविधा प्रदाता के रूप में राज्य की बदलती भूमिका के अनुसार होना चाहिए।

(क) जवाबदेहता तथा कुशलता के संबंधित प्रयास

(क) भर्ती → भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना के माध्यम से प्रशासनिक शिक्षा

→ लैटरल एंट्री को बढ़ावा (बासवान कमेटी)

→ विशेषज्ञता का समावेश

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ भर्ती प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु बासवन कमेटी के सुधार।

(ख) प्रशिक्षण – नैतिक प्रशिक्षण – 2nd ARC की 4th रिपोर्ट, शासन में नैतिकता के अनुसार प्रशिक्षण में अनिवार्य परिवर्तन।
- विदेशी राष्ट्रों से सीख (फिनलैंड मॉडल)।
- मिशन कर्मयोगी (भूमिका आधारित प्रशिक्षण)।

(ग) मूल्यांकन – होता समिति के अनुसार 14, 20 वर्ष पर मूल्यांकन (360° मूल्यांकन)
- अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रावधान।
- भूमिका आधारित पदोन्नति।
- कार्य निष्पादन मानक की स्थापना।
- सिविल सेवक परफॉर्मेंस इंडेक्स

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आवश्यकता के कारण

① प्रशासनिक भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, क्रोनी कैपिटलिज्म का बढ़ता प्रभाव।

② 'बाबी सदी के अनुकूल' न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन'

③ सुविधा प्रदाता के रूप में राज्य तथा लोककल्याणकारी राज्य (नीतिनिर्देशक तत्व)

④ अनु॰ 311 के कारण मजबूत नौकरशाही को संरक्षण।

अतः होता समिति, शासन में नैतिकता रिपोर्ट (2nd ARC) के अनुरूप नौकरशाही को जनकेंद्रित, संवेदनशील, नैतिक मूल्यों से युक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Despite initiatives taken by the Indian government to achieve critical goals in the education sector, major interventions are required to tackle learning poverty as well as the persisting inequalities. Discuss. **(250 words) 15**

शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पहलों के बावजूद, लर्निंग पॉवर्टी (अधिगम निर्धनता) के साथ-साथ विद्यमान असमानताओं से निपटने के लिए बड़े हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

सतत विकास लक्ष्य-4 (गुणवत्तायुक्त शिक्षा) तथा अनु. 21क (शिक्षा का अधिकार) शिक्षा के विकास को अनिवार्य बनाते है। एनजीओ प्रथम की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लर्निंग पावर्टी विद्यमान है (असर रिपोर्ट)

लर्निंग पावर्टी से तात्पर्य उच्च कक्षा के बालकों द्वारा गणित तथा सामान्य विषयों के प्रति समझ की कमी से है।

★ भारत सरकार के प्रयास

① नई शिक्षा नीति, २०२० – शिक्षा को बहुमुखी बनाना तथा बच्चों को विषय अपनाने की स्वतंत्रता।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② समग्र शिक्षा अभियान, 2000 → प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का समग्र विकास।

③ उच्चतर शिक्षा अभियान → विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता तथा शोध व अनुसंधान पर बल।

④ निष्ठा, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

* बड़े हस्तक्षेपों की आवश्यकता के कारण

① कोविड-19 के कारण डिजिटल डिवाइड के कारण बच्चों का पिछड़ना (आंध्रप्रदेश में 2 लाख बच्चे फेल)

② शिक्षा की अनुपातमी गुणवत्ता (ग्रामीण स्तर पर विद्यमान विसंगतियाँ- असर रिपोर्ट)

③ शिक्षा में अपर्याप्त सार्वजनिक एवं निजी निवेश (खराब अवसंरचना)

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) उच्च शिक्षा के सीमित अवसर

(5) रोजगार विहीन शिक्षा (नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 45.6% स्नातक ही रोजगार योग्य।)

(6) शिक्षा का भोजन, आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार से जुड़ा होना।

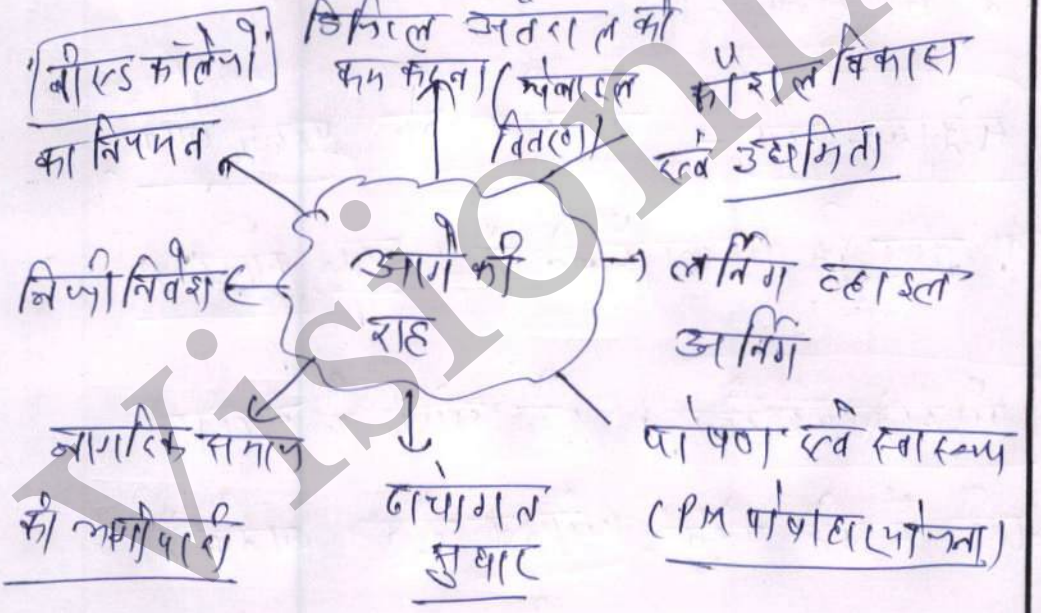

अतः शिक्षा वह हथियार है जिसका उपयोग सामाजिक विकास के रूप में किया जा सकता है (कोफी अन्नान)

VisionIAS

18. In light of the burgeoning burden of both communicable and non-communicable diseases, there is a need to revamp the public health surveillance system in India. Discuss. **(250 words) 15**

संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार के रोगों के बढ़ते बोझ के आलोक में, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुसार भारत में 80% मौतें गैर संचारी रोगों के कारण होती हैं, जिसे 2025 तक घटाकर 25% करने का लक्ष्य है।

* संक्रामक रोग → वे रोग जो प्रत्यक्ष संपर्क, हवा, वायु के कारण फैलते हैं। उदा० कोविड-19

* गैर संक्रामक रोग → ये संपर्क के कारण नहीं फैलते परंतु, जीवन हेतु घातक है। उदा. T.B. (WHO के अनुसार विश्व के 1/3 मामले भारत में)

* सुधार की आवश्यकता

① आउट ऑफ पॉकेट खर्च तथा

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बढ़ती मंहगाई के कारण आम आदमी की पहुँच से दूर।

② अपर्याप्त स्वास्थ्य ढाँचा → 22.5/10,000 स्वास्थ्य कर्मी, जबकि वैश्विक औसत 45/10,000

→ नागरिक-बेड अनुपात कम (1 बेड, वैश्विक औसत से कम)

→ अपर्याप्त चिकित्सक (1404 लोगों पर 1 चिकित्सक, WHO 1/1000)

③ राज्यों की सीमित क्षमता → PHC, CHC के पर्याप्त उपकरण का अभाव।

④ कम मेडिकल सीटें → बच्चों का विदेश पढ़ने जाना (यूक्रेन संकट)

⑤ शहरी क्षेत्र में 75% चिकित्सा सुविधाएं जबकि केवल 31% जनसंख्या।

⑥ जलवायु परिवर्तन के कारण रोगों का बढ़ता अनुपात।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपाय ① प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे का उन्नयन (क्यूबा मॉडल)

② डॉक्टर-मरीज अनुपात WHO मानकों के अनुरूप

③ स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाकर GDP का 2.5% करना

④ सार्वजनिक एवं निजी निवेश को प्रोत्साहन

⑤ मेडिकल शिक्षा ढांचे का उन्नयन (उच्च शिक्षा पर कस्तूरीरंगन पैनल)

⑥ आयुष्मान भारत/डिजिटल हेल्थ मिशन

⑦ संक्रामक एवं गैरसंक्रामक रोगों हेतु शोध व अनुसंधान (ICMR की क्षमता में बढ़ोतरी)

'पहला सुख निरोगी काया' के अनुरूप स्वास्थ्य ढांचे का उन्नयन सतत विकास तथा सामाजिक न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण कदम होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. The repercussions of the ongoing economic crisis in Sri Lanka extend beyond its borders. Discuss with specific reference to India. Also, mention the steps that India has taken to assist Sri Lanka tide over the crisis.

(250 words) 15

श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट का प्रभाव उसकी सीमाओं से परे भी पड़ रहा है। भारत के विशिष्ट संदर्भ में विवेचना कीजिए। साथ ही, उन कदमों का भी उल्लेख कीजिए जो भारत ने इस संकट से निपटने में श्रीलंका की सहायता के लिए उठाए हैं।

श्रीलंका तथा भारत के सम्बंध 2500 वर्षों से अधिक पुराने व्यापारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कारकों से प्रेरित है।

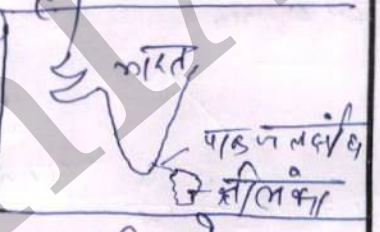

* हालिया संकट के कारण

① FDI नकारात्मक (ईस्टर बम विस्फोट।

② कृषि उत्पादन (रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर प्रतिबंध।

③ चीन की ऋण जाल कूटनीति (हम्बनटोटा बंदरगाह)

④ आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता।

* संकट के प्रभाव बाहर भी

→ श्रीलंका चाय का महत्वपूर्ण उत्पादक एवं निर्यातक।

→ चीन की ऋण जाल कूटनीति उजागर।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

+ वैश्विक संरक्षणवाद के कारण छोटे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की क्षति।

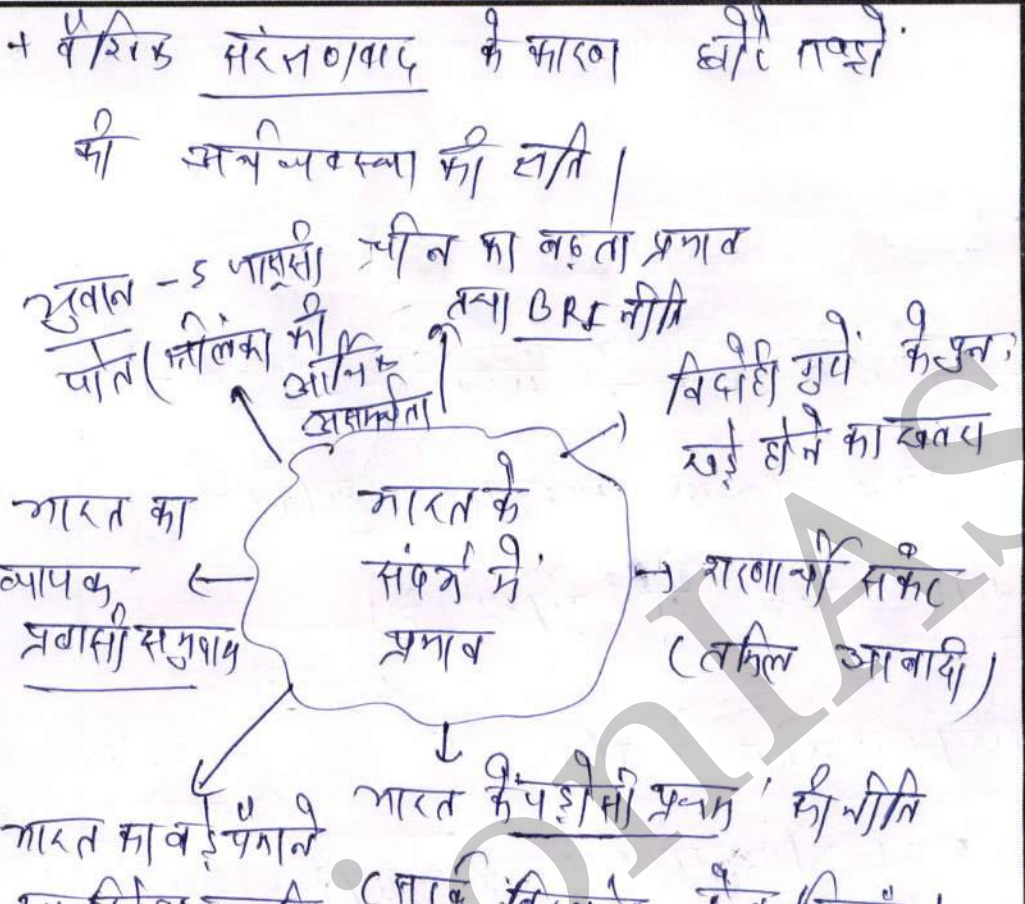

* भारत द्वारा उठाए गए कदम

① खाद्यान्न तथा तेल आवश्यकताओं की तत्काल आपूर्ति

② जेनरिक दवाओं का निर्यात (श्रीलंका 85% आयात पर निर्भर)

③ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट

④ 500 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट।

⑤ आपातकालिक सहायता हेतु 'गुजराल सिद्धांत' के अनुरूप सहायता।

आगे की राह ① क्षेत्रीय शांति एवं समृद्धि हेतु सांस्कृतिक संवाद।

② बिम्सटेक सहयोग, नेबरहुड फर्स्ट के तहत सहायता

③ लोगों का लोगों से संपर्क को बढ़ाना

④ चीन के प्रभाव को संतुलित करना।

अतः 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के मूल्यों के अनुरूप तत्काल सहायता तथा गुजराल सिद्धांतों के तहत पड़ोसी सहायता की नीति का पालन वर्तमान की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India is a reliable partner in the Indian Ocean Region and can take on the role of being the net security provider in the region. Discuss.

(250 words) 15

भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार है और इस क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता होने की भूमिका निभा सकता है। विवेचना कीजिए।

भारत ने शांगरी ला डायलॉग (2018) के तहत मुक्त, खुले, समावेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुपालन आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात की।

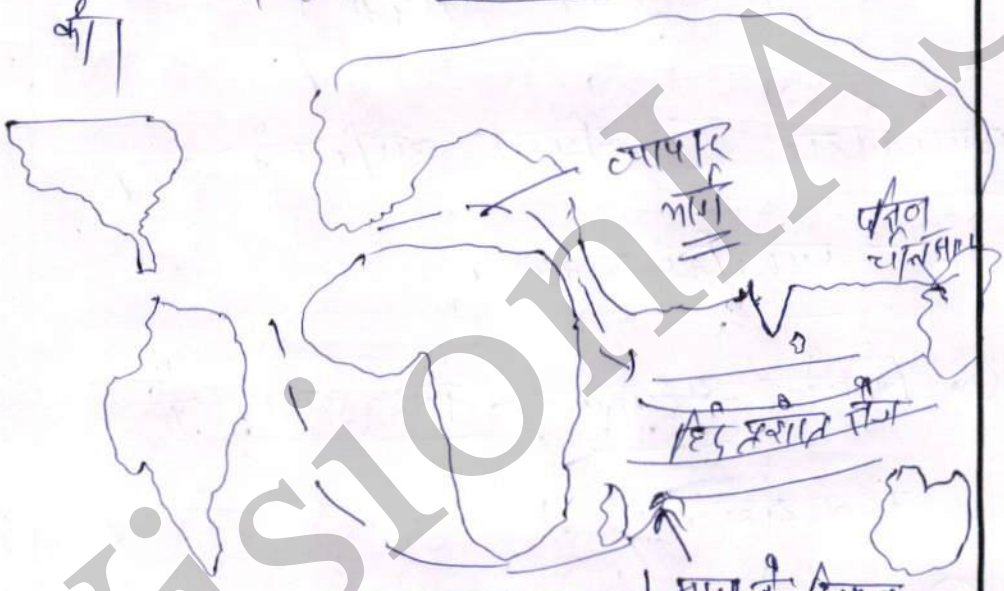

(A) भारत विश्वसनीय भागीदार

① हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (2008) के तहत समुद्री सुरक्षा।

② बिम्सटेक तथा सार्क के तहत दक्षिण-दक्षिण सहयोग।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

③ हिंद-प्रशांत विज़न के तहत UNCLOS के अनुसार शासित व्यवस्था का पक्षधर।

④ हिंद महासागर रसोसिएशन के तहत सहयोग।

* समग्र सुरक्षा प्रदाता के तत्व

① सैन्य सहायता (हथियार आपूर्ति)
② सैन्य प्रशिक्षण (मालदीव, नेपाल की सेना का प्रशिक्षण)
③ सैन्य कूटनीति (युद्धाभ्यास)
④ सैन्य तैनाती (पड़ोसियों एवं आपातकालीन संकट)

* चुनौतियाँ (i) सीमित संसाधन तथा चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता।
(ii) पिछली तैनाती के अनुभव (श्रीलंका, मालदीव में विरोध)

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) गुट निरपेक्षता की नीति से विचलन

(iv) USA की नीति में बदलाव (AUKUS का गठन)

(v) विस्तृत हिंद महासागर तथा व्यापक हित।

आगे की राह → ① एशियाई सुरक्षा, ग्लोबल कॉमन्स का संरक्षण, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था

② द्विपक्षीय - बहुपक्षीय सहयोग (विश्वसनीय पार्टनर)

③ आर्थिक एवं डिप्लोमेसी

④ सांस्कृतिक संबंध एवं सॉफ्ट पावर

अतः हिंद महासागर हेतु भारत-प्रशांत नीति के साथ संतुलन स्थापित कर गुटनिरपेक्षता 2.0 के अनुरूप वैश्विक नेतृत्व के रूप में भारत की सकारात्मक भूमिका की आवश्यकता है।

VisionIAS